सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ` 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 31 दिसंबर, 2025
वर्षः 03, अंकः 5, पृष्ठः 8+4

योगी मंत्रिमंडल में मकर संक्रांति के बाद फेरबदल!

इनसाइड कलेक्ट्रेट तक डेड बॉडी लेकर कैसे पहुंचे प्रदर्शनकारी? »Pg03

» Pg 12

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ

रामलला की नगरी में भक्ति-वैभव का अद्भुत संगम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी से राम मंदिर तक किया पूजन, अन्नपूर्णा मंदिर पर फहराई धर्मध्वजा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी आज एक बार फिर इतिहास की साक्षी बनी, जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भव्य धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मनाई गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी पहुंचकर श्रद्धा, संकल्प और संस्कृति का अनुपम संदेश दिया।

दोनों नेताओं ने समारोह की शुरुआत हनुमानगढ़ी से की, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती हुई। इसके पश्चात वे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में रामलला के दर्शन के बाद रक्षा मंत्री ने दंडवत प्रणाम किया।

रामलला के दर्शन के बाद रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री परकोटा स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्मध्वजा फहराई गई। यह क्षण ऐतिहासिक रहा, क्योंकि परकोटा के मंदिरों में पहली बार धर्मध्वजा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्वजा पूजन, पुष्प अर्पण, धूप-दीप आरती और जलाभिषेक के साथ संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गद्दीनसीन महंत प्रेम दास जी से आशीर्वाद लिया । दोनों नेताओं का संत समाज द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वे अंगद टीला पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता के साथ जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

राम केवल आस्था नहीं, राष्ट्र के संस्कार

- प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर रामलला का सरयू जल, पंचामृत व केसर-दूध से अभिषेक, 56 भोग अर्पण, स्वर्णाभूषणों से श्रृंगार और स्वर्ण जड़ित पीतांबर धारण कराकर विशेष सज्जा की गई। पूरे आयोजन का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया गया। श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि रखी गई है। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, जिसने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी। आज उसकी द्वितीय वर्षगांठ पर अयोध्या ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि राम केवल आस्था नहीं, राष्ट्र के संस्कार हैं।

नोटिस के बाद भी नहीं जमा हुआ टैक्स, दो खाते सीज निकासी पर पूर्ण रोक

27 करोड़ टैक्स बकाए पर आयकर विभाग ने लुलु मॉल के बैंक खाते किए फ्रीज

मुख्य संवाददाता/स्वराज इंडिया

लखनऊ। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुलु मॉल के बैंक खातों पर शिकंजा कस दिया है। करीब 27 करोड़ रुपये के टैक्स बकाया मामले में विभाग ने मॉल के दो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ आयकर विभाग के उपनिदेशक (सर्किल-1) द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब मॉल प्रशासन इन खातों से किसी भी प्रकार की राशि निकाल नहीं सकेगा। हालांकि खातों में रकम जमा की जा सकेगी।

सूत्रों के अनुसार, लुलु मॉल पर लंबे समय से टैक्स बकाया चल रहा था। इस संबंध में आयकर विभाग ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन न तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही बकाया टैक्स जमा हुआ। इसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए खाते सीज कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार बकाया टैक्स राशि जमा होने के बाद ही खाते दोबारा संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

वर्ष 2025 में कानपुर मेट्रो ने रची इंजीनियरिंग की नई इबारत, 2026 में बड़े विस्तार की तैयारी

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। वर्ष 2025 कानपुर मेट्रो के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी रहा। शहर को अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात मिलने के साथ ही आधुनिक शहरी परिवहन की दिशा में कानपुर ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। आने वाले नए वर्ष में दक्षिण कानपुर को मेट्रो कॉरिडोर का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे लाखों नागरिकों को यातायात में राहत मिलेगी।

कॉरिडोर-एक के अंतर्गत आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक यात्री सेवाएं पहले ही आरंभ हो चुकी हैं। अब अगला लक्ष्य नौबस्ता तक मेट्रो संचालन का है। इस विस्तार के साथ मेट्रो नेटवर्क में दो नए अंडरग्राउंड स्टेशन झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर तथा पांच एलिवेटेड स्टेशन बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता जुड़ेंगे। जनवरी 2026 में शेष बचे इस सेक्शन पर टेस्ट रन शुरू होने की संभावना है।

कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल के पास रैंप तक लगभग तीन किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन में टनलिंग कार्य अक्टूबर 2025 में पूरा कर लिया गया था।

इसके बाद दोनों लाइनों पर ट्रैक निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। वहीं बारादेवी से नौबस्ता तक पांच किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में ट्रैक निर्माण पूरा हो चुका है और सिग्नल प्रणाली की टेस्टिंग जारी है। मेट्रो परिचालन और स्टेशनों की बिजली आपूर्ति के लिए छह नए सब-स्टेशन तैयार कर उन्हें ऊर्जीकृत भी कर दिया गया है।

कॉरिडोर-दो, जो सीएसए से बर्रा-आठ तक प्रस्तावित है, पर भी निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग आठ दशमलव छह शून्य किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में पाइलिंग, पिलर और पियर-कैप निर्माण अंतिम चरण में है। प्रीकास्ट गर्डरों का निर्माण और इरेक्शन कार्य भी तेज गति से चल रहा है।

रावतपुर से डबल पुलिया तक अंडरग्राउंड सेक्शन में दोनों लाइनों पर टनलिंग कार्य पूरा हो चुका है, जबकि काकादेव से डबल पुलिया तक शेष टनलिंग कार्य प्रारंभिक 2026 में पूरा होने की उम्मीद है।

वर्ष 2025 में कानपुर मेट्रो को कई सम्मान भी प्राप्त हुए।

चुन्नीगंज से ट्रांसपोर्ट नगर तक स्थित सभी अंडरग्राउंड स्टेशनों को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग दी गई। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

दक्षिण कानपुर तक मेट्रो के पहुंचने से विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा इलाका

यूपी मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कानपुर मेट्रो परियोजना केवल संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि शहर के भविष्य को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास है। दोनों कॉरिडोर पूरे होने के बाद यातायात जाम से राहत मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और कानपुर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।नए वर्ष में दक्षिण कानपुर तक मेट्रो के पहुंचने से यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से और मजबूती से जुड़ जाएगा, जिससे शहर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

बच्चे से कुकर्म, आरोपी को लिया हिरासत में

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जूही क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर पड़ोस में रहने वाला 16 वर्षीय किशोर बच्चे को बहाने से अपने घर ले गया और कमरे में ले जाकर गलत हरकत की। कुछ देर बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा तो वह खून से लथपथ था। उसने मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे।सूचना पर पुलिस जब आरोपित के घर पहुंची तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे हिरासत में ले लिया। जूही थाना प्रभारी के.के. पटेल ने बताया कि मां की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

रजिस्ट्री कार्यालय में आयकर का सर्वे 1000 करोड़ के बैनामा में मिली गड़बड़ी

10 दिन का समय दिया, नोटिस देकर जवाब मांगा

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आयकर विभाग ने कानपुर रजिस्ट्री कार्यालय में 1000 करोड़ के बैनामों में गड़बड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें गलत पैन कार्ड और अधूरी प्रविष्टियों के जरिए टैक्स चोरी की कोशिश की गई थी। कानपुर में आयकर विभाग की आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण (आईएनसीआई) ने रजिस्ट्री कार्यालय में उपनिबंधक द्वितीय में सर्वे किया। इस दौरान आयकर अधिकारियों को सैकड़ों बैनामों में विसंगतियां मिलीं। इन बैनामों की रकम 1000 करोड़ रुपये बताई गई है, जिससे करोड़ों रुपये के राजस्व को हानि पहुंची है। आयकर अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी को 10 दिन का नोटिस देकर जवाब मांगा है। आयकर सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को आईएनसीआई की टीम ने दोपहर में रजिस्ट्री कार्यालय के उपनिबंधक द्वितीय में सर्वे की कार्रवाई की।

यह कार्रवाई रजिस्ट्री कार्यालय की ओर से दाखिल वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) की प्रविष्टियों में गलतियों की वजह से की गई। रजिस्ट्री कार्यालय ने बैनामों की जानकारी देते समय कई गलतियां की जिससे आयकर विभाग के रडार से सैकड़ों लोग बाहर हो गए। अब विभाग ऐसे लोगों का सही पैन कार्ड नंबर पता कर रहा है।

वहीं, कई ऐसे भी बैनामे मिले हैं जिनमें पैन कार्ड गलत लिखा है। उसकी जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय से मांगी गई है। यह कार्रवाई तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली। सर्वे में आयकर अधिकारियों ने बड़े स्तर पर कागज कब्जे में लिए हैं।अभी सैकड़ों रजिस्ट्री के कागजात मौके पर नहीं मिलने के कारण उपनिबंधक प्रथम को 10 दिन का समय दिया गया है कि वह जल्द से जल्द सभी मांगे गए कागजातों को कार्यालय मुहैया कराएं। यह कार्रवाई आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), कानपुर के मार्गदर्शन में सहायक निदेशक विमलेश राय और आयकर अधिकारी अविनाश सोनवानी की अगुवाई ने आयकर निरीक्षक आयकर निरीक्षक कुलदीप गुप्ता, बिनोद केशरी, राजेंद्र कुमार एवं अंकित श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही।

कलेक्ट्रेट तक डेड बॉडी लेकर कैसे पहुंचे प्रदर्शनकारी?

कलेक्ट्रेट के बाहर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करने से डीएम नाराज

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

- कार्रवाई के आश्वासन पर माने परिजन
- चूक पर शासन को लेटर, जांच करेंगे तीन आलाधिकारी

कानपुर। कलेक्ट्रेट में लाश रखकर प्रदर्शन और पुलिस की लापरवाही का मामला अब तूल पकडता जा रहा है। कचहरी में छुट्टी के दिन जब भीड कम थी तो भी पुलिसकर्मी या गेटों पर तैनात कर्मियों को डेड बॉडी ले जाते लोग नहीं दिखे। इस पूरी चूक पर डीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है।

आलाधिकारियों का कहना है कि आखिर प्रदर्शनकारी डेड बॉडी लेकर कलेक्ट्रेट कैसे पहुंचे क्या इसकी जानकारी एलआईयू या पुलिस विभाग को नहीं थी। डीएम ने इस संबंध में शासन से शिकायत की बात कही है। वहीं पूरे मामले की जांच को तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

इनपुट के अनुसार कलेक्ट्रेट में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी मच गई जब कुछ लोग एक डेड बॉडी लेकर वहां पहुंच गए। डेड बाडी को रखकर लोग नारे लगाने लगे। आननफानन पहुंचे प्रशासनिक अफसरों को बताया कि मृतक का नाम राम गोपाल उम्र 45 है, केशवनगर का रहने वाला है। आरोप लगाया कि बीते रोज चश्ट ने जबरन वहां के लोगों को बेघर कर दिया था, वह पास में ही तिरपाल डालकर रह रहे थे।

सोमवार देर रात ठंड से राम गोपाल की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी राजेश कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण जानने के बाद मुआवजे का आश्वासन दिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जो लोग बेघर उनके रहने के लिए फौरी तौर पर निकट के रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की जाएगी।

केडीए पर क्या हैं आरोप

- परिजनों का आरोप है कि 16 दिसंबर 2025 को केडीए जोन 3 की प्रभारी अधिशासी अभियंता माधवी कुशवाहा की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मकान को तोड़ दिया। वह पास में ही तिरपाल डालकर रह रहे थे। सोमवार देर रात ठंड से राम गोपाल की मौत हो गई। मृतक की बेटी ज्योति ने बताया कि उनके पिता की ठंड से मौत हुई है। इसके बाद यह लोग दाह संस्कार के पहले प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए।

तीन सदस्यीय कमेटी गठित

- मामले में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने तीन सदस्यीय कमेटी की गठन किया है, जिसमें एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार, केडीए सचिव वऔर अपर नगर आयुक्त को शामिल किया है। यह कमेटी मकान गिरने से लेकर मौत तक की जांच करेगी। डीएम ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। यदि शीतलहर से मौत हुई है तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

डीएम ने कहा-जांच करेगी कमेटी

- ठंड से मौत का मामला और कलेक्ट्रेट में बाडी लेकर प्रदर्शन को लेकर डीएम ने खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह एलआइयू की नाकामी है कि उन्हें पता नहीं चला कि ऐसा होना वाला है। इस संबंध में शासन को भी लेटर लिखेंगे।

हर रास्ते में हैं पुलिस की ड्यूटी फिर भी कलेक्ट्रेट का ये हाल

कानपुर। शव को लेकर परिजनों द्वारा डीएम आफिस लाने के कई रास्ते हैं, जिसमें कचहरी गेट, कलेक्ट्रेट गेट (लायर्स एसोसिएशन के पास), सदर तहसील गेट व वीआईपी रोड स्थित नया गेट है। इन सभी गेट्स पर न्यायालय सुरक्षा व कलेक्ट्रेट की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है। किसी भी स्थिति में कचहरी या कलेक्ट्रेट में लाश लाने का मतलब नहीं उठता। क्योंकि इस कैंपस से किसी श्मशान घाट या कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं जाता है।

ऐसे में चार कंधों पर आ रही अर्थी को देखकर मन में सवाल उठना लाजमी है। ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों के मन में भी सवाल तो जरुर उठा होगा लेकिन किसी ने आगे बढ़कर यह पूछना जरुरी नहीं समझा कि यह अर्थी कहां जा रही है।

कलेक्ट्रेट में बॉडी लेकर प्रदर्शन की सूचना के बाद सक्रिय हुआ एलआईयू विभाग के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार समेत कई थानों की फोर्स मौके पर आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने पाई।वहीं जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी पहले फूलबाग के बाहर कुछ देर बैठे, जहां से वह दाह संस्कार को जाने की तैयार कर रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने लाश वाहन को कलेक्ट्रेट की ओर कर दिया। मौजूद लोगों ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग के पास वाहन खडा कर वहां से डेड बॉडी को कलेक्ट्रेट की ओर ले गए।

कानपुर सेंट्रल पर एक करोड़ की चरस के साथ विदेशी तस्कर व महिला गिरफ्तार

आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की संयुक्त कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने संयुक्त कार्रवाई में कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 10 किलोग्राम चरस के साथ एक विदेशी तस्कर और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है।

एनसीबी लखनऊ से सूचना मिली कि एक पुरुष और एक महिला ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर कानपुर पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर आरपीएफ कानपुर सेंट्रल और एनसीबी की संयुक्त टीम ने स्टेशन के कैंट साइड निकास द्वार पर यात्रियों की निगरानी शुरू की। इसी दौरान एक महिला और एक पुरुष को रोके जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शक गहराने पर दोनों को आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में पुरुष ने अपना नाम राम पुकार निवासी पर्सा (नेपाल) बताया। उसकी पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 500-500 ग्राम के 20 पैकेटों में कुल 10 किलोग्राम चरस बरामद हुई। महिला ने अपना नाम राजमती देवी निवासी बेतिया (बिहार) बताया।

जीएसवीएम के मनोचिकित्सक खंगालेंगे आईआईटी में आत्महत्याओं की वजह

स्वराज इंडिया फालोअप

- परिवार की शिकायत आई तो शामिल की जाएगी जांच दायरे में उपनिदेशक, रिपोर्ट जल्द सौंपेगी टीम

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में बीटेक छात्र जयसिंह मीणा की आत्महत्या मामले की जांच के लिए संस्थान ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति का नेतृत्व जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. धनंजय चौधरी करेंगे। आईआईटी प्रशासन ने इसकी अधिसूचना मंगलवार शाम जारी की।

आईआईटी के उपनिदेशक प्रो. ब्रजभूषण ने बताया कि समिति छात्र के अकादमिक प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी उपलब्ध जानकारी, साथ ही मित्रों, सहपाठियों, परिवार और शिक्षकों से बातचीत कर तथ्य जुटाएगी। यदि परिवार किसी पर आरोप लगाता है या कोई अतिरिक्त शिकायत देता है तो उसे भी जांच के दायरे में शामिल किया जाएगा।सूत्रों

के अनुसार छात्र ने पहले सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग में कुछ काउंसलिंग सत्र में हिस्सा लिया था, हालांकि बीते महीनों से वह नियमित संपर्क में नहीं था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इससे पहले छात्र या परिवार की ओर से संस्थान को कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दी गई थी। पुलिस और आईआईटी प्रशासन मिलकर घटना की जांच कर रहे हैं।

आईआईटी में छात्र जय सिंह मीणा की मौत पर एनएचआरसी में शिकायत

» सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर पंकज कुमार सिंह ने विस्तृत सूचनाओं के संकलन के साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को घटना रिपोर्ट की है

बीते साल वर्ष 2024 में याची ने रिट दाखिल कर आईआईटी में हुई आत्महत्या की घटनाओं की जाँच कर न्याय की मांग की थी, इसी रिट में छात्र जय सिंह मीणा की मौत प्रकरण को शामिल कर जाँच की मांग की है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। आवास विकास केशव पुरम निवासी पेशे वरिष्ठ सूचना तकनीकी अभियंता पंकज कुमार सिंह ने आईआईटी छात्र जय सिंह मीणा की मौत के मामले की रिपोर्ट एनएचआरसी को भेज दी है। उन्होंने बीते साल वर्ष 2024 में याची ने रिट दाखिल कर आईआईटी में हुई आत्महत्या की घटनाओं की जाँच कर न्याय की मांग की थी, इसी रिट में छात्र जय सिंह मीणा की मौत प्रकरण को शामिल कर जाँच की मांग की है। पंकज ने अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी को अवगत कराया है कि आईआईटी प्रशासन लगतार एक दशक से अधिक समय से छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के प्रयासों के दावे करता है जबकि रोकथाम के कोई सतही असर नहीं दिखाई दिए हैं। जबकि छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की तीव्रता बढ़ी है, और ऐसी घटनाएं अब साल ही नहीं महीनों में घटित हो रहीं हैं।

घटनाएं लगातार आईआईटी प्रशासन के प्रशासकीय फेल्योर सहित गंभीर अनियमितता, लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शा रहा है कि छात्र की मौत के 12 –14 घंटे बाद घटना की सूचना पता चल सकी। उल्लिखित करते हुए बताया कि पिछली कुछ माह पूर्व छात्र धीरज सैनी की आत्महत्या की घटना 2 –3 दिन बाद पता चल सकी थी तब जब छात्र के कमरे से बदबू आना शुरू हो गई दी

और शव के अपशिष्ट कमरे से बहार आगये थे। घटनाएं लगातार आईआईटी प्रशासन के प्रशासकीय फेल्योर सहित गंभीर अनियमितता, लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शा रहा है कि छात्र की मौत के 12 –14 घंटे बाद घटना की सूचना पता चल सकी जैसा की पुलिस प्राथमिक जाँच और खबरों से ज्ञात हुआ है ।

याची ने आईआईटी की सुरक्षा व्यवस्था और काउंसलिंग सेल पर बडा सवाल उठाते हुए आईआईटी प्रशासन को कटघरे में खडा किया है। याची ने छात्र जय सिंह मीणा की मृत्यु की इस सूचना को लंबित रिट केस में शामिल कर न्याय हित की कार्रवाई में आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

हत्या या किसी के दवाब में उठता कदम ?

मेरे भाई पर पर पढाई का कोई दवाब नहीं था। लेकिन जब भी उससे बात हुई वह किसी के डर , दबाब में दिखता था। वह पूंछा करता था किसी प्रोफ़ेसर , सीनियर या आईआईटी ऑफिस से कोई फोन तो नहीं आया ? इसपर वह यकीन के लिए कसम लेकर पूंछता था। यह गंभीर मामला है कुछ असलियत है जो सामने नहीं आई है। वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। यह बात मृतक छात्र की बहन ने कही है। मंगलवार को मृतक छात्र के परिजन आईआईटी कैम्पस में पहुंचे।

आईआईटी को 22 जनवरी को देने होंगे जवाब

याची पंकज कुमार सिंह की आपत्तियों पर आईआईटी कानपुर को एनएचआरसी कोर्ट में 22 जनवरी को जवाब देने का आदेश पारित किया गया था। पिछले वर्ष 30 दिनों के भीतर तीन छात्रों की आत्महत्या की घटना सहित विगत 19 वर्षों में घटित समस्त घटनाओं के पीड़ित परिजनों को न्याय के लिए जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी।

एनएचआरसी ने केंद्र के मानवसंसाधन मंत्रालय शिक्षा विभाग, विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सहित आईआईटी कानपुर के निदेशक को तलब करते हुए नोटिस जारी किये थे। आईआईटी ने 18 बिंदुओं पर अपने ज़वाब पेश किये थे जिसपर याची आपत्ति जताई कि दावे मुख्यतः नीतिगत व घोषणात्मक है, जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता है।

तीन से हाड़कंपाऊ ठंड होगी शुरू,14 के बाद आएगी कमी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर 4.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां 14 जनवरी तक शीतलहर और पाले का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य बनी हुई है और प्रदूषण का स्तर सामान्य से चार गुना तक अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में कानपुर की रात सबसे ठंडी रही। रात का तापमान 2.2 डिग्री लुढ़ककर 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दिन का पारा एक डिग्री गिरकर 15.9 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार कंपकंपाती ठंड और कोहरे से नए साल की शुरुआत में भी राहत नहीं मिलेगी। पहली तारीख और दो जनवरी को दोपहर में हल्की धूप निकल सकती है।सुबह से ही धुंध और उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंडक बढ़ी रहेगी। चार बजे के बाद से फिर शीतलहर शुरू हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार, तीन जनवरी के बाद लगातार 14 जनवरी तक शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। रात में शीतलहर की स्थिति पूरे कानपुर मंडल में रह सकती है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह तक ठंड के साथ कोहरा, धुंध और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तीन जनवरी से रात के समय पाला पड़ना शुरू हो सकता है। ऐसे में लोगों के साथ फसलों को भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए फसलों में नमी बनाए रखने के सुझाव दिए गए हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कोरारी, पोस्ट मंगटा, थाना गजनेर, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात निवासी आदर्श सिंह पुत्र प्रदीप सिंह का आधार कार्ड संख्या 9880 3863 6722 में नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र प्रदीप सिंह अंकित है, जबकि शपथकर्ता के समस्त शैक्षिक अभिलेखों में नाम आदर्श सिंह दर्ज है।शपथकर्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनका वास्तविक एवं प्रचलित नाम आदर्श सिंह है तथा भविष्य में उन्हें आदर्श सिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चंद्र प्रकाश पुत्र बैजनाथ निवासी भौरा हमीरपुर(यूपी)का मूल आवंटन पत्र (डी/5592/दिनांक 18.01.2014) प्लाट न. E 374 EWS हाइवे सिटी विस्तार पार्ट 2 कानपुर नगर कहीं खो गया है, जिसका प्रयोग किसी अन्य के द्वारा अवैध माना जाएगा। यदि किसी को उक्त अभिलेख प्राप्त हों तो कृपया निम्न नंबर पर संपर्क करें। मो.9935371931

सार्वजनिक सूचना

मैं, भूतपूर्व सैनिक संख्या 13980985 एम रैंक-हवलदार / एए, नाम करन सिंह, पुत्र सरदार सिंह, निवासी मकान संख्या 4क्र427, आवास विकास, हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर नगर (यूपी), पिन कोड 208021, आम जनमानस को यह सार्वजनिक रूप से सूचित करता हूँ कि मेरी पत्नी का वास्तविक एवं वैध नाम राज बाला सिंह है तथा उनकी जन्म तिथि 03.04.1971 है। भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर-शासकीय, बैंक, बीमा, संपत्ति, शैक्षिक अभिलेखों व कार्यों में उक्त नाम एवं जन्म तिथि से ही जाना और माना जाए।

सार्वजनिक सूचना

मैं, भूतपूर्व सैनिक संख्या 14666112ह, रैंकङ्गनायक, नाम अनूप कुमार, पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम एवं पोस्ट कोरियां, तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 209206, आम जनमानस को यह सार्वजनिक रूप से सूचित करता हूँ कि मेरी पत्नी का वास्तविक एवं वैध नाम अनीता है तथा उनकी जन्म तिथि 15.08.1987 है। भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर-शासकीय, बैंक, बीमा, संपत्ति, शैक्षिक अभिलेखों व कार्यों में उक्त नाम एवं जन्म तिथि से ही जाना और माना जाए।

सम्पादकीय

शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि एक सुधार

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। निश्चित ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए।दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह 'ऑपरेशन पवन' की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है। चूंकि ऑपरेशन पवन में शहीद हुए कई सैनिकों का अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया विदेशी धरती पर पूरी हुई थी, इसलिए उनके परिजन शहीद सैनिकों के अवशेषों को वापस भारत लाने की नीति को सुव्यवस्थित करने की मांग करते रहे हैं। वे एक ऐसे आयोग के गठन की भी मांग करते रहे हैं जो शहीद सैनिकों के पार्थिव अवशेष को वापस भारत लाने की नीति को तार्किक बना सके।

खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है अरावली का वजूद

डा. देवेन्द्र शर्मा

एक अरब साल से भी ज्यादा पुरानी अरावली पहाड़ियों ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान बनने के विरुद्ध एक हरी दीवार का काम किया है। ये पहाड़ियां समृद्ध जैव विविधता का भंडार भी हैं; ये जमीन के नीचे के जलभंडारों की... एक अरब साल से भी ज्यादा पुरानी अरावली पहाड़ियों ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान बनने के विरुद्ध एक हरी दीवार का काम किया है। ये पहाड़ियां समृद्ध जैव विविधता का भंडार भी हैं; ये जमीन के नीचे के जलभंडारों की भरपाई करने में अहम भूमिका निभाती हैं और इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेगिस्तान की आगे बढ़ने की चाल को रोका है।वर्ष 2021 की हॉलीवुड व्यंग्य फिल्म 'डोंट लुक अप' में, दो अमेरिकी खगोलशास्त्री दुनिया को एक धूमकेतु के बारे में चेतावनी देते हैं, जो पृथ्वी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति एक अरबपति के झांसे में आ जाते हैं, जो यह दावा करता है कि उस आकाशीय पिंड में खरबों डॉलर के दुर्लभ तत्व हैं। आखिरकार, धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है, जिससे एक वैश्विक आपदा बनती है।

काश! फिल्म के मुख्य किरदारों ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के भयानक परिणामों के बारे में संज्ञान लिया होता, जैसा कि उत्तर भारत के 'हरे फेफड़े' पुकारी जाने वाली और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील किंतु क्षतिग्रस्त की जा चुकी अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रस्तावित 100 मीटर की परिभाषा से साफ था तो फिल्म का शीर्षक 'डोंट लुक अप, लुक डाउन' होता। यह वही है, जिसकी चेतावनी महात्मा गांधी ने यह कहकर दी थी, 'दुनिया में हर किसी की ज़रूरत के लिए काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं।' कई साल पहले, मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर जलाशय के ऊपर हिमालय की नाजुक पहाड़ियों में चूना पत्थर की खुदाई पर रिपोर्टिंग करने गया था। एक सीमेंट कंपनी धीरे-धीरे, परत-दर-परत, चूना पत्थर वाली पहाड़ी को खुरच रही थी। जब मैंने कंपनी के महाप्रबंधक से पूछा कि क्या उन्हें अहसास है कि पहाड़ी को समतल करने से गंभीर पारिस्थितिक नुकसान होगा, तो उनके जवाब में आमतौर पर हावी मानसिकता झलक रही थी, 'जब पहाड़ी ही नहीं रहेगी तो आप किस पारिस्थितिक नुकसान की बात कर रहे हैं हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित सभी विकास गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मुख्य आवश्यक तत्वों के अत्यधिक खनन के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं और इसके लिए सख्त नियमों के अलावा प्रकृति द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन की भी ज़रूरत है। इसके सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, जिनके लिए कोई माप-सूत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में, अगर नीति निर्माताओं को गलती करनी भी पड़े, तो उन्हें लोगों और पर्यावरण के हित में गलती करनी चाहिए। इसी तरह, जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगे, तब एक ऐसा कथानक गढ़ने की कोशिश की गई जो उन दावों को चुनौती दे रहा था, जिसमें इस घटनाक्रम को जलवायु आपदा बताया गया था। भगवान का शुक्र है कि अब दुनिया पिघलते ग्लेशियरों के विनाशकारी परिणामों के प्रति जाग गई है। ग्लोबल वार्मिंग से आगे बढ़कर, दुनिया पहले ही ग्लोबल बॉइलिंग स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में 1.44 लाख वर्ग किमी में फैली अरावली पहाड़ियों में सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा और बेशक, संगमरमर जैसे मुख्य खनिजों का भरपूर भंडार है। इसके अलावा, ये पहाड़ियां लिथियम, निकेल, मोलिब्डेनम, नाइओबियम और टिन जैसे ज़रूरी खनिजों से भी भरपूर हैं। जैसे 'डोंट लुक अप' में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया गया था कि धूमकेतु की आर्थिक संपत्ति बहुत ज्यादा दौलत लाएगी, वैसे ही यह माना जा रहा है कि अरावली में मौजूद खनिज आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी हैं।

देश के अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में अहम उड़ान

एलवीएम3-एम6 का प्रक्षेपण

शशांक द्विवेदी

इसरो द्वारा एलवीएम3-एम6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण प्रमाण है कि भारत तकनीक और क्षमता के बल पर नई दिशा तय कर रहा है। यह वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ ही देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस लॉन्च का अनुभव गगनयान मिशन की तैयारी में मददगार होगा। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वह केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता राष्ट्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा एलवीएम3-एम6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण यह साबित करता है कि भारत अब केवल एक सीखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी तकनीक और क्षमता के बल पर नई दिशा तय कर रहा है।

यह सफलता केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की सोच, नीति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। भारत ने जब अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन भारत भारी उपग्रहों को अपने दम पर अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। आज उपग्रह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल संचार, इंटरनेट, मौसम की जानकारी, टीवी प्रसारण, कृषि सलाह, आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा—इन सभी में अंतरिक्ष तकनीक की अहम भूमिका है। एलवीएम3 जैसे शक्तिशाली रॉकेट यह भरोसा देते हैं कि देश अब अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है।

एलवीएम3 भारत का सबसे ताकतवर प्रक्षेपण यान है। पहले इसे जीएसएलवी मार्क-3 के नाम से जाना जाता था। इसका उपयोग भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। एलवीएम3-एम6 इस रॉकेट का छठा सफल मिशन है, जिसमें उपग्रह को तय योजना के अनुसार सुरक्षित रूप से उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन की सफलता यह दिखाती है कि इसरो की तकनीक अब पूरी तरह से भरोसेमंद हो चुकी है। एलवीएम3 रॉकेट तीन चरणों में काम करता है। पहले चरण में ठोस ईंधन वाले दो बड़े बूस्टर रॉकेट को तेजी से ऊपर ले जाते हैं। दूसरे चरण में तरल ईंधन वाला इंजन रॉकेट को स्थिर गति देता है। तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन काम करता है, जो उपग्रह को सटीक कक्षा में पहुंचाता है। भारत के लिए क्रायोजेनिक तकनीक लंबे समय तक चुनौती रही, लेकिन आज यह पूरी तरह स्वदेशी बन चुकी है।

एलवीएम3-एम6 मिशन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की एक सशक्त मिसाल है। इस रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश तकनीक और उपकरण देश में ही विकसित किए गए हैं। इससे विदेशी निर्भरता कम हुई है, साथ ही, देश में उच्च तकनीकी उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। यह उपलब्धि बताती है कि भारत जटिल तकनीकों को समझने और विकसित करने में सक्षम है। अब भारत का सपना है कि वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजे। इस सपने को पूरा करने के लिए गगनयान मिशन पर काम चल रहा है। एलवीएम3 रॉकेट इसी मिशन की रीढ़ है। एलवीएम3-एम6 से मिले अनुभव और आंकड़े मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में मदद करेंगे। इससे रॉकेट की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन को और बेहतर बनाया जा सकेगा। अंतरिक्ष आज विज्ञान का ही क्षेत्र नहीं रहा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। संचार उपग्रह, निगरानी उपग्रह व नेविगेशन सिस्टम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। एलवीएम3 जैसे रॉकेट भारत को यह ताकत देते हैं कि वह अपने रणनीतिक उपग्रह खुद लॉन्च कर सके। इससे देश की सुरक्षा और मजबूत होती है।

18 दिन बाद टूटा गतिरोध

अधिवक्ताओं की एकजुटता रंग लाई

एसडीएम तहसील परिसर में उपनिबंधक कार्यालय बनाने की घोषणा करते हुए।

बिल्हौर बार एसो0अध्यक्ष विधायक को मिठाई खिलाते हुए।

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील परिसर से उप-निबंधन कार्यालय को बाहर स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन 18 दिन बाद आखिरकार समाप्त हो गया। जिला प्रशासन ने अधिवक्ताओं की मांगों को स्वीकार करते हुए उप-निबंधन कार्यालय का नया भवन तहसील परिसर में ही बनाए जाने का निर्णय लिया है। इस घोषणा के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि सुभानपुर गांव में उप-निबंधन कार्यालय शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव के

⇨ तहसील परिसर में ही बनेगा उपनिबंधन कार्यालय, आंदोलन समाप्त

विरोध में बिल्हौर बार एसोसिएशन और द लायर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता बीते 18 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि कार्यालय के तहसील परिसर से बाहर जाने पर वादकारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था और आम जनता के दैनिक कार्य भी प्रभावित होंगे।

हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह ठप हो गया था। अधिवक्ता प्रतिदिन रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन को सांसद अशोक रावत, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक राहुल बच्चा सोनकर, जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान, सभासदों, किसान यूनियन, कानपुर बार एसोसिएशन, कानपुर ग्रामीण प्रेम क्लब अध्यक्ष तथा बार काउंसिल सदस्य अनुराग पांडेय का भी समर्थन मिला।

एकजुट संघर्ष का मिला सकारात्मक परिणाम

- अधिवक्ताओं ने इस फैसले को अपनी एकजुटता और लंबे संघर्ष की जीत बताया तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी भी बिल्हौर तहसील पहुंचे और अधिवक्ताओं को बधाई दी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजेश कटियार और लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार ने कहा कि यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं बल्कि आम जनता के हित में भी है। लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने से अब तहसील परिसर में सामान्य कार्य व्यवस्था बहाल हो सकेगी।

मंगलवार को जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर उपजिलाधिकारी बिल्हौर डॉ. संजीव कुमार दीक्षित धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम ने जिलाधिकारी के निर्देशों से अवगत कराते हुए घोषणा की कि उप-निबंधन कार्यालय का नया भवन तहसील परिसर में ही बनाया जाएगा। घोषणा होते ही अधिवक्ताओं ने विधायक और एसडीएम का फूल-मालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही आंदोलन समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी गई।

स्वराज इंडिया बिल्हौर 06

मिट्टी खनन के वर्चस्व की जंग में दो पक्ष भिड़े, चली गोली

वर्चस्व को लेकर फायरिंग मामले में 22 पर केस दर्ज, इलाके में तनाव

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर(कानपुर)। सोमवार शाम चौबेपुर कस्बे के एक पेट्रोल पंप पर अवैध खनन और इलाके में वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। विवाद हाथापाई और फायरिंग तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष लंबे समय से खनन के वर्चस्व को लेकर आमने-सामने थे। सोमवार को विवाद गाली-गलौज से शुरू होकर हाथापाई और फायरिंग तक बढ़ गया। पीड़ित रंजीत ने बताया कि वह पेट्रोल पंप पर डीज़ल लेने आए थे, तभी उन

⇨ अवैध खनन और इलाके में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हुई थी मारपीट व फायरिंग

पर हमला किया गया। कट्टे से फायरिंग की गई, लेकिन वह किसी तरह बच गए।

थानाध्यक्ष ने बताया कि घायल रंजीत की तहरीर पर सुनौढ़ा गांव के संजय सिंह, अजय सिंह, बोझा गांव के ध्यानू सिंह, करतरिया गांव के भोले सिंह, महाराजपुर के मोनू पाल, दिनेश सिंह, विपिन चौरसिया और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

पांडु नदी पर पुल बनने से खत्म होगा 14 किमी का चक्कर

⇨ कसिगवां पंचायत के करीब 25 हजार लोगों के लिए राहत
⇨ लोक निर्माण विभाग बनाएगा तीन मीटर चौड़ा पुल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर। कसिगवां पंचायत के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। सरकार ने पांडु नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 5 करोड़ 56 लाख 51 हजार रुपये की लागत आएगी और इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाएगा।पुल बनने के बाद ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय ककवन पहुंचने के लिए अब 14 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग सिर्फ डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर कार्यालय तक पहुंच सकेंगे।

कसिगवां ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कुल पांच गांव हैं, जिसमें मकरंदी नेवादा, नया नेवादा, अंटवा और भवन नेवादा शामिल हैं।

पहले इन गांवों के लोग पंचायत पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करते थे। साल 2021 में इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था। तब अधिकारियों ने आश्वासन देकर स्थिति शांत कराई थी।

पुल का लाभ सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अंता, नेवादा मितई, गुदैला, रामपुर तालुका, मल्लपुर, पिम्मा नेवादा सहित कई अन्य गांवों के करीब 25 हजार लोग इससे सीधे प्रभावित होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता के मुताबिक जनवरी माह से पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा।

सीडीओ विधान जायसवाल ने संभाली कमान, विकास को नई रफ्तार की उम्मीद

नवागत सीडीओ की सख्त कार्यशैली से प्रशासन में सक्रियता

शंकर सिंह/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। जनपद के विकास कार्यों को नई दिशा और गति देने के उद्देश्य से नवागत मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने कार्यभार संभालते ही अपनी सक्रिय और अनुशासित कार्यशैली का परिचय दिया। पहले दिन उन्होंने विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों और अनुभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अभिलेखों के संधारण, फाइलों की स्थिति और कार्य प्रगति की बारीकी से समीक्षा की तथा सभी दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए गुणवत्ता, नियमित निगरानी और आपसी समन्वय के साथ कार्य करना अनिवार्य है। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ

बैठक कर शासन की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जनपद के समग्र विकास के लिए टीम भावना के साथ कार्य करने पर बल दिया गया।मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन में साफ-सफाई, समय पालन और कार्य अनुशासन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। नवागत सीडीओ की इस सक्रियता और सख्त रुख से प्रशासनिक अमले में नई ऊर्जा और कार्य के प्रति गंभीरता देखने को मिली है।

पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ससुराल में लगाई फांसी

परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के बनीपारा जिनई गांव में बीते मंगलवार रात एक युवक ने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

मृतक की पहचान मैनपुरी जिले के किशनी क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी हृदयराम के रूप में हुई है। वर्ष 2021 में रूरा थाना क्षेत्र के बनीपारा जिनई गांव निवासी घंटू सविता की पुत्री सरिता से हृदयराम की शादी हुई थी।वह गुजरात में किसी निजी कंपनी में नौकरी करता था।बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब आठ बजे हृदयराम का अपनी पत्नी सरिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद सरिता अपने बच्चों शिवांश,आराध्या और नैना को लेकर घर के बाहर अपनी मां के साथ बैठ गई।कुछ देर बाद जब वह कमरे में लौटी तो उसने अपने पति हृदयराम को दुपट्टे के सहारे पंखे के कुंडे में लटका पाया।घटना की जानकारी होने पर परिजन तथा ग्रामीण मौके पर पहुंचे।परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी अमित शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

जनसुनवाई में एसपी का सख्त तेवर, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

कानपुर देहात माती। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने कार्यालयों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, मारपीट, उत्पीड़न सहित विभिन्न मामलों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए।

पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक प्रकरण की बारीकी से समीक्षा करते हुए संबंधित थाना प्रभारियों व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फरियादियों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों को आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाएगा।

पुखरायां स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के सेवानिवृत्त होने पर समारोह

कानपुर देहात। पुखरायां रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर तैनात नरेंद्र कुमार वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार को उनके सहयोगी कर्मचारियों ने एक समारोह में उपहार भेंट कर भावभीनी विदाई दी।अमृत रेलवे स्टेशन में शुमार पुखरायां रेलवे स्टेशन पर 2017 से तैनात हुए स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र कुमार वर्मा 30 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। साथी कर्मचारियों ने मंगलवार को उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। स्टेशन अधीक्षक देवेंद्र सिंह , स्टेशन अधीक्षक केके दीक्षित, घाटमपुर के अधीक्षक वीके चंदोला, समेत सभी ने सेवा निवृत्त हुए स्टेशन अधीक्षक के सुखद एवं मंगलमय जीवन हेतु सुभेक्षा प्रकट की। स्टेशन अधीक्षक वीके प्रजापति, दीपक कुमार, अवधेश कुमार, संजय यादव, वीके पांडेय, अजय यादव, मुहम्मद आरिफ, पूर्व स्टेशन अधीक्षक देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह सचान, वीके पांडेय, एस एस सिसोदिया भी मौजूद रहे।

एक स्थान पर दो-दो बना दिए कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन

पार्षद ने संसाधनों के बिना बने ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्रों की जांच की मांग उठाई

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम के वार्ड संख्या 23 कल्याणपुर आवास विकास क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। पार्षद राम नारायण कुरील ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को पत्र भेजकर बिना संसाधनों के बनाए गए इन केंद्रों पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

पार्षद का कहना है कि आवास विकास तीन के विभिन्न स्थानों पर ठेकेदार श्री राम इंफ्राटेक द्वारा एक ही वार्ड में क्षमता से अधिक नौ स्थानों पर ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्रों का निर्माण कराया गया है, जो आवश्यकता से कहीं अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर एक ही जगह दो-दो केंद्र बना दिए गए हैं, जो नियमों के विरुद्ध है और निजी स्वार्थ को दर्शाता है।उन्होंने यह भी बताया कि बनाए गए केंद्रों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। नौ में से केवल चार केंद्रों पर ही आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं, जबकि शेष केंद्र निष्प्रभावी पड़े हैं। कई स्थानांतरण केंद्र बंद अवस्था में हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य बिना वास्तविक जरूरत और संसाधनों के कराया गया।पार्षद राम नारायण ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जो नियमों के अनुसार गलत है। उन्होंने वार्ड में आवश्यकता से अधिक बनाए गए ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्रों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

इसी प्रकार पनकी भाटिया होटल के पास कालपी रोड पर बनाया गया स्थानांतरण केंद्र भी उपयोग में नहीं आ पा रहा है, जिससे योजना की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।इस मामले में नगरस्वास अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह गौर ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से केंद्र बनाए गए हैं अभी हो सकता है उतना प्रयोग ना हो रहा हो लेकिन जल्दी उनका प्रयोग किया जाएगा।

कानपुर में कड़ाके की ठंड अलाव की डिमांड बढ़ी

दक्षिण कानपुर के कई इलाकों में अलाव और रेन बसेरों की मांग की जा रही है

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच नगर निगम की ओर से अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में राहगीर, मजदूर और बेसहारा लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर अलाव की व्यवस्था न के बराबर है।

वार्ड 82, जरौली फेज 2 क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। यहां न तो अलाव की व्यवस्था है और न ही रैन बसेरा की कोई सुविधा। लगातार बढ़ती ठंड के बीच यह क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से 1 भी स्थान पर अलाव नहीं जलवाया गया।

ऐसे में समाजसेवी और स्थानीय व्यापारियों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है। आनंद साउथ सिटी के सामने कटियार मेडिकल स्टोर, लक्ष्मी ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, शक्ति ऑटो मोबाइल्स, रोहन और रंजीत फेब्रिकेशन तथा सोम टाइल्स के सहयोग से पिछले कई दिनों से लगातार अलाव जलवाए जा रहे हैं। इन अलावों से क्षेत्रवासियों के साथ-साथ राहगीरों को भी ठंड से राहत मिल रही है।

क्षेत्रवासी प्रहलाद कुमार ने बताया कि कड़ाके की ठंड में प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे में गरीब और बेसहारा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विनय विश्वकर्मा और सौरभ शर्मा का कहना है कि अलाव की व्यवस्था करना नगर निगम का काम है, लेकिन जरौली क्षेत्र में इसके नाम पर 1 लकड़ी तक नहीं जलाई गई।

कटियार मेडिकल स्टोर के संचालक राजेश कटियार ने बताया कि नगर निगम द्वारा हमारे क्षेत्र में अलाव नहीं जलवाए जा रहे हैं, जिससे आम जनमानस सर्दी से परेशान है। गरीब परिवारों के लोगों को सर्दी से बचाने के लिए लक्ष्मी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर शिवम बाजपेई एवं बालाजी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर जगजीवन यादव के सहयोग से करीब 40 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक दिन मुख्य मार्ग पर अलाव जलवाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी एवं राहगीर ठंड से राहत पा सकें।

बता दें बसंत पेट्रोल पंप से कटियार मेडिकल स्टोर तक नगर निगम की ओर से कोई अलाव नहीं जलवाया गया है। सर्दी बहुत बढ़ गई है, जिससे सबसे ज्यादा राहगीर और बेसहारा लोग परेशान हो रहे हैं। उनके लिए प्रशासन को शीघ्र अलाव जलवाना चाहिए।

आज राम अवतार कटियार, जगजीवन यादव, शिवम बाजपेई, शोभित बाजपेई, योगेंद्र कुमार सचान, रमेश सिंह, मुन्नी लाल विश्वकर्मा, प्रहलाद कुमार, विनय विश्वकर्मा, हनीब, महेश, शीलू आदि क्षेत्रवासी अलाव तापते मिले, साथ ही कई राहगीर थोड़ी-थोड़ी देर अलाव तापकर अपने-अपने कार्यों के लिए जाते दिखे।

कानपुर शहर के कई इलाकों में अलाव की मांग लगातार बढ़ रही है।

अकबरपुर कस्बे में पैसे लेकर फुटपाथ पर लगवाए जा रहे ठेला

»जनहित के नाम पर अवैध उगाही का मुद्दा नगर पंचायत बोर्ड बैठक में उठा

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।अकबरपुर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में नगर की गंभीर यातायात समस्या और अवैध उगाही का मामला प्रमुखता से उठाया गया। सभासद निर्लेप बबलू भारती ने बैठक में कहा कि अकबरपुर जनपद का मुख्यालय होने के कारण नगर में प्रतिदिन चारों ओर से लोगों का आवागमन होता है। जिला अस्पताल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, अग्निशमन केंद्र, तहसील, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, निजी विद्यालय, स्टेडियम सहित अनेक कार्यालय नगर में स्थित होने से यातायात का दबाव लगातार बना रहता है।सभासद ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से अकबरपुर चौराहे के आसपास निजी भूमि के मकान मालिक और दुकानदार अपने-अपने मकानों के सामने ठेला लगवाकर अवैध रूप से धन की उगाही कर रहे हैं। आरोप है कि ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों से प्रतिदिन दो सौ से तीन सौ रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ठेले लगवाए जा रहे हैं, वहां सड़क, नाला, प्रकाश व्यवस्था और सफाई की जिम्मेदारी नगर पंचायत निभा रही है, लेकिन आर्थिक लाभ निजी लोगों को हो रहा है। इससे न केवल नगर पंचायत को नुकसान हो रहा है, बल्कि लगातार जाम की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।सभासद निर्लेप बबलू भारती ने जनहित को देखते हुए सुझाव दिया कि पहले ऐसे मकान मालिकों और दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए, जो अपने मकान और दुकान के सामने ठेले लगवाकर अवैध उगाही कर रहे हैं। साथ ही ठेला लगाने की व्यवस्था को नियमानुसार सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि नगर को जाम से राहत मिल सके और छोटे व्यापारियों का शोषण भी बंद हो।बैठक में उठे इस मुद्दे के बाद नगर में अवैध उगाही पर कार्रवाई की उम्मीद जगी है। आम जनता ने भी मांग की है कि नगर प्रशासन इस विषय पर शीघ्र ठोस कदम उठाए, ताकि अकबरपुर को जाम और अव्यवस्था से मुक्ति मिल सके।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 l **Email:** swarajindia2023@gmail.com l **Mob:** 7800009853, l **Website:** www.swarajindianews.com l (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

संगीत सोम के कड़वे बोल, कहा

शाहरुख खान देश का गद्दार

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ। दौराला में आयोजित जनसभा में पूर्व विधायक संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए अभिनेता शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष और कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर भी निशाना साधा। मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने जन शताब्दी समारोह के तहत आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला में जनसभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का मुद्दा जोरशोर से उठाया।

» अभिनेता शाहरुख खान पर साधा निशाना

» प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना

» अपराध और कानून-व्यवस्था पर दावा

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इसके बावजूद कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है।

संगीत सोम ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका भी उनका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्राओं में 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं साथ जाती हैं और भारत का मान बढ़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं—फ्री राशन, घर-घर शौचालय और उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर से विरोधी दल बौखला गए हैं।

पूर्व विधायक ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश के कुछ लोग क्रिकेट और फिल्मों के जरिए राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है और शाहरुख खान द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को साढ़े नौ करोड़ रुपये में खरीदने का आरोप लगाया। संगीत सोम ने अभिनेता को गद्दार बताते हुए कहा कि देश ने उन्हें पहचान दी है और अब ऐसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है।संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हुए दावा किया कि प्रदेश में गुंडों का सफाया किया गया है। वर्ष 2013 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय बहन-बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं, जबकि आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ईवीएम को गलत बताया गया और अब मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बदनाम किया जा रहा है। संगीत सोम ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा साढ़े तीन सौ से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष 20ङ्क30 सीटों तक सिमट जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में गद्दारों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

भीषण सर्दी में भी जनसुनवाई में तत्पर एसपी आरती सिंह

» निर्धारित समय पर प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर वह नियमित रूप से जनसुनवाई में जुट जाती हैं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। कड़ाके की ठंड और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के बावजूद जनपद में तैनात पुलिस अधीक्षक आरती सिंह आमजन की समस्याओं के प्रति लगातार संवेदनशील बनी हुई हैं। शासन द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर वह नियमित रूप से जनसुनवाई कर रही हैं, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय की उम्मीद मिल रही है।बुधवार को भी पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में दूर-दराज से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर उन्होंने तत्काल, निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों और पीड़ितों ने बताया कि अत्यधिक सर्दी के बावजूद पुलिस अधीक्षक का समय पर कार्यालय पहुंचना और गंभीरता से समस्याएं सुनना सराहनीय है। लोगों ने उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे प्रशासनिक प्रयासों से आमजन का भरोसा मजबूत होता है।लगातार जनसुनवाई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आरती सिंह यह संदेश दे रही हैं कि मौसम की कठिनाइयां भी जनता की समस्याओं के समाधान में बाधा नहीं बन सकतीं। उनकी यह सक्रियता और संवेदनशीलता जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिस और जनता के बीच विश्वास को भी बढ़ा रही है।

हृदय विदारक घटना

महोबा में मानवता को झकझोर देने वाली हुई घटना

संपत्ति के लालच में मौत से पहले पांच साल की कैद, भूख और यातना का दर्दनाक सच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

महोबा। महोबा जिले से सामने आई यह खबर न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज और व्यवस्था दोनों के लिए कठोर सवाल खड़े करती है। सत्तर वर्षीय ओम प्रकाश राठौर, जो वर्ष दो हजार पंद्रह में रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे, वर्ष दो हजार सोलह में पत्नी के निधन के बाद अपनी इकलौती बेटी रश्मि के साथ रह रहे थे। घर में देखभाल के लिए उन्होंने राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को रखा था। लेकिन यही भरोसा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया।

आरोप है कि नौकर दंपती ने धीरे-धीरे ओम प्रकाश की संपत्ति पर नजर गड़ा ली। चालाकी से घर पर कब्जा किया और पिता-पुत्री को अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया। यह अमानवीय कैद पूरे पांच वर्षों तक चलती रही। इस दौरान अगर कोई मिलने आता, तो नौकर यह कहकर टाल देता कि साहब बाहर गए हैं। अंदर क्या चल रहा है, इसकी भनक किसी को नहीं लग सकी।

अब ओम प्रकाश की मौत के बाद यह खौफनाक सच्चाई सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनकी मौत लंबी कैद, भूख, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तथा इलाज न मिलने के कारण हुई। मौत ने उस राज से पर्दा उठा दिया, जो वर्षों तक चार दीवारों के भीतर दबा रहा।इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली हालत सत्ताईस वर्षीय बेटी रश्मि की है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रश्मि जीवित तो थी, लेकिन उसकी हालत किसी अस्सी साल की बुजुर्ग से भी बदतर थी। शरीर पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था। बदन पर मांस

नहीं के बराबर था, कपड़े तक नहीं थे। बस सांसें चल रही थीं। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखें नम हो गईं और रूह कांप उठी।घटना के उजागर होते ही नौकर पति-पत्नी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश जारी है। घर, मृतक ओम प्रकाश, उनकी बेटी रश्मि और जांच में जुटी पुलिस की तस्वीरें सामने आई हैं। पीड़ितों की हालत की तस्वीरें अत्यंत संवेदनशील हैं।

यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस सामाजिक चुप्पी और लापरवाही का आईना है, जिसमें इंसान इंसान पर ही जुल्म करता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई। महोबा की यह कहानी लंबे समय तक लोगों के दिलों और दिमागों को झकझोरती रहेगी।

सच का कैमरा ऑन होते ही बौखलाया निर्मला अस्पताल का प्रबंधन पत्रकार से मारपीट व लूट

अब कानून के शिकंजे में निर्मला हॉस्पिटल, पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी और कवरेज के दौरान कैमरा व माइक छीनने के मामले में साकेतपुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल के कर्मियों के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई वीडियो जर्नलिस्ट राजा की तहरीर पर की गई है।बताया जाता है कि राजधानी लखनऊ और अयोध्या के कुल पांच अस्पतालों में गंभीर लापरवाही की आशंका को उजागर करने वाली खबर के प्रसारण के बाद अस्पताल प्रबंधन बौखला गया था। इसी क्रम में बीते दिन कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की गई, उनका कैमरा और माइक छीन लिया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया और अयोध्या के साकेतपुरी स्थित निर्मला हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके बावजूद अस्पताल कर्मियों की दबंगई का मामला अब आपराधिक शक्ल में सामने आया है। कोतवाली में दर्ज लूट के मुकदमे ने न केवल संबंधित अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ा दी है, बल्कि अन्य निजी अस्पतालों में भी हड़कंप मचा दिया है। पत्रकारों पर हमले को लेकर पुलिस की यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश मानी जा रही है कि सच उजागर करने वालों को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छह करोड़ रुपये की लागत से नगर निगम कराएगा दो कुंडों का कायाकल्प

महापौर ने की घोषणा

» 2.64 करोड़ रुपये की लागत से होगा दुर्गा कुंड का नवनिर्माण

» 3.34 करोड़ की लागत से होगा अमृत जलाशय सुख सागर का निर्माण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम छह करोड़ रुपये की लागत से नगर में दो प्रमुख तालाबों का कायाकल्प कराएगा। इस कार्यक्रम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने समारोहपूर्वक शिलान्यास किया और चौपाल लगाकर जनसुनवाई की। प्रकाश, पेयजल समेत कई समस्याओं का समाधान किया।

महापौर ने झलकारी बाई वार्ड स्थित अष्टभुजा देवी मंदिर कुशमाहा में 2.64 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गा कुंड के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य छह माह में पूरा होना है। इस मौके पर पार्षद खुशीराम, मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, रामकुमार, शोभाराम, त्रिभुवन, मनिंदर सिंह, गुड्डू यादव, अष्टभुजी मंदिर के महंत रोहित दास, योगेंद्र वर्मा पूर्व प्रधान, राजबक्स सिंह, राजकपूर सिंह, परशुराम पूर्व प्रधान, शक्ति केंद्र संयोजक अजय गौड़, सुनील सिंह, गजेंद्र यादव, गुड्डू सिंह, रवि तिवारी, युवा मोर्चा के सौरभ मिश्र, रामजी वर्मा, परशुराम भारती, राणा सिंह, श्याम बहादुर सिंह, लक्ष्मण वर्मा मौजूद रहे।लाला लाजपत राय वार्ड के बड़ा गद्दोपुर में अमृत-2 परियोजना के तहत अमृत जलाशय सुखसागर का शिलान्यास महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नारियल फोड़कर किया। उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया। यह कार्य नौ माह में पूरा होना है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि सिल्ट हटाकर बांध का निर्माण, बाउंड्री वॉल, टो-वाल, दो घाट, पथ-वे, शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, रिचार्ज पिट, स्ट्रीट लाइट, बेंच, उद्यान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भगवान शंकर की फौव्वारायुक्त प्रतिमा भी स्थापित होगी।

मानकविहीन विकास कार्यों की पहचान बनती अयोध्या

» नगर निगम परिसर में सी एंडडीएस का निर्माण: 18.70 करोड़ की योजना, सवालों के घेरे में

» मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी- परियोजना प्रबंधक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को वैश्विक नगरीय मॉडल बनाने के सरकारी दावों के बीच विकास कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर कठघरे में खड़ी है। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष ने नगर निगम अयोध्या परिसर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार और मानकविहीन निर्माण का बड़ा आरोप लगाया है। सरोज यादव का कहना है कि अयोध्या में जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं, वे केवल कागजों और फाइलों में मानक के अनुरूप हैं, जबकि

जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

जिलाध्यक्ष के अनुसार मुख्यमंत्री वैश्विक नगरीय योजना के अंतर्गत अयोध्या नगर निगम के पुराने कार्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें— 3-डी शो मॉडलिंग वातानुकूलित परिसर,ओपन एयर थिएटर,रेन वाटर हार्वेस्टिंग,मूर्तियों की स्थापना,ड्रिप इरिगेशन,वेंडर जोन,प्रोजेक्शन लाइट और साउंड शो जैसे आकर्षक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 18.70 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस (जल निगम) है और टेंडर अद्भुत डिजाइन एंड इनोवेशन, फैजाबाद को दिया गया है। लेकिन आरोप है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की नींव ही मानकों को ताक पर रखकर डाली जा रही है। आरोप है कि निर्माण कार्य में मलबा डालकर पीसीसी कराई जा रही है मिट्टी और दलदल के ऊपर सीधे आरसीसी गिट्टी डाल दी गई। आरसीसी बेस में कार्यालय मरम्मत से निकली सुरखी और चुना तक डाला जा रहा है।यदि ये आरोप सही हैं, तो यह न सिर्फ निर्माण मानकों का खुला उल्लंघन है, बल्कि करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि से भविष्य का खतरा खड़ा करने जैसा है।

नगर निगम ने झाड़ा पल्ला

मामले को और गंभीर बनाता है नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया। नगर निगम की मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग) पुनीत ओझा का कहना है कि इस कार्य से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, न ही हमें कोई जानकारी है। नगर निगम परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य से मुख्य अभियंता को जानकारी न होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।

सी एंड डीएस का जवाब - बजट का हिस्सा नहीं

सी एंड डीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत से बात करने पर उन्होंने कहा कि फाउंडेशन में हो रही पीसीसी उनके बजट का हिस्सा नहीं है नगर निगम द्वारा जगह उपलब्ध न कराए जाने से कार्य प्रभावित हो रहा है।यदि जगह मिल जाए, तो 8 महीने में पूरा कार्य करा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के अंतर्गत पुराने कार्यालय में एग्जिबिशन म्यूजियम, दुकानें,रेस्टोरेंट दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुरानी मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा और कुछ नई मूर्तियों का अनावरण भी प्रस्तावित है। मानकविहीन कार्य के सवाल पर परियोजना प्रबंधक का कहना है कि मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब काम चल रहा है, तब जांच क्यों? क्या पहले मानकों की अनदेखी होगी और बाद में कागजी जांच से मामला निपटा दिया जाएगा ?

ठंड से बचाव के लिए सरकारी राहत 'ऊंट के मुंह में जीरा'

आपदा विभाग की योजना नाकाफी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

» सरकारी कम्बल सिर्फ रजिस्टर में बंटते हैं, गरीब तक नहीं पहुंचते

अयोध्या ।रामनगरी इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। गलियों, चौराहों, फुटपाथों और बस अड्डों पर ठिठुरते बेसहारा, मजदूर, बुजुर्ग और निराश्रित लोग सरकार की आपदा राहत योजना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ठंड से बचाव के लिए बनाई गई सरकारी व्यवस्था आंकड़ों में तो भारी-भरकम है, पर ज़मीन पर ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।

जिला प्रशासन भले ही लगातार बचाव और राहत कार्यों के दावे कर रहा हो, लेकिन सदर तहसील से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ठंड से जूझ रहे जरूरतमंदों की हालत बदतर बनी हुई है।

सदर तहसील के अंतर्गत नगर निगम द्वारा लगभग 150 स्थानों पर अलाव जलाने और 1000 कम्बल वितरण का दावा किया जा रहा है। नगर निगम सीमा से बाहर तहसील प्रशासन लेखपालों के माध्यम से अलाव जलवाने की बात कह रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील क्षेत्रों

में एक-दो दिन अलाव जलाकर फोटो भेज दी जाती है और उसके बाद महीनों तक न तो अलाव दिखते हैं, न प्रशासन। कम्बल वितरण की स्थिति और भी चिंताजनक है। कागजों में वितरण पूरा, लेकिन जरूरतमंद आज भी ठंड में भटक रहे हैं। कई इलाकों में तो लोगों ने साफ कहा—सरकारी कम्बल सिर्फ रजिस्टर में बंटते हैं, गरीब की देह तक नहीं पहुंचते। विडंबना यह है कि जहां सरकारी तंत्र की रफ्तार ठिठुर रही है, वहीं कई स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन अपने संसाधनों से कम्बल वितरण कर रहे हैं। स्थानीय लोग सवाल पूछ रहे हैं अगर स्वयंसेवी संस्थाएं यह काम कर सकती हैं, तो करोड़ों के बजट वाला आपदा प्रबंधन तंत्र क्यों नहीं?

तहसीलदार का बयान बनाम ज़मीनी सच्चाई

सदर तहसीलदार धर्मेन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि नगर निगम सीमा से बाहर उनके क्षेत्र में 10 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और 7 नए स्थल बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी गई है। कम्बल वितरण पर उनका दावा है कि 1642 कम्बल की आपूर्ति हो चुकी है, जिनमें से 1200 कम्बल वितरित किए जा चुके हैं। शेष कम्बल जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं और 1000 कम्बल की अतिरिक्त मांग भेजी गई है।अलाव के बजट पर तहसीलदार का बयान और भी चौंकाने वाला है। उनके अनुसार,अलाव के लिए 50 हजार की धनराशि आती है, जिसे लेखपालों को भुगतान कर दिया जाता है। फिलहाल धनराशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेखपाल अपने पास से लकड़ी जलवा रहे हैं। तहसीलदार के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में लेखपाल अपने वेतन से अलाव जलवा रहे हैं और बाद में भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं? या फिर यह बयान भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह सिर्फ कागजों में ही सुंदर दिखता है? अयोध्या के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बयान और आंकड़ों का खेल तहसील प्रशासन और लेखपालों के लिए नया नहीं है। अलाव गिनाने में, कम्बल जोड़ने में और फाइलें भरने में यह तंत्र पहले से ही माहिर माना जाता रहा है।

बांग्लादेश में तीसरे हिंदू की हत्या

चुनाव के पहले खौफ का माहौल

मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में बढ़ा हमला, पीट-पीटकर और गोली मारकर की जा रही हत्याएं

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। बांग्लादेश में आम चुनावों से पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या, फिर 24 दिसंबर को राजबाड़ी शहर में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की माब लिंचिंगऔर अब मेमनसिंह के भालुका उपजिला में सोमवार को बजेंद्र बिस्वास (40) को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 10 दिनों के भीतर हिंदू समुदाय के तीन लोगों की हत्या से देश में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र नाथ ने बजेंद्र बिस्वास की हत्या की पुष्टि की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे मेहराबाड़ी इलाके स्थित सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री परिसर में हुई। यहां पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के सदस्य नोमान मियां ने बजेंद्र को गोली मार दी।

अमृत मंडल, दीपू चंद्र दास, बजेन्द्र बिस्वास।

पुलिस ने आरोपी नोमान को गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त फैक्ट्री में अंसार के करीब 20 जवान ड्यूटी पर मौजूद थे। बताया गया कि बजेंद्र और नोमान साथ बैठे थे तभी नोमान की शॉटगन से गोली चली, जिससे बजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। बजेंद्र सिलहट सदर उपजिला के कादिरपुर गांव निवासी प्रोबित्र बिस्वास के पुत्र थे।

लगातार हत्याओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बढ़ती हिंसा ने अल्पसंख्यकों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि अंतरिम सरकार पर कानून-व्यवस्था संभालने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

सबसे पहले दीपू चंद्र दास की हुई थी मॉब लिंचिंग

- बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच हाल ही में दीपू चंद्र दास नाम के युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय हिंदू समुदाय में दहशत का माहौल है।स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विवाद के बाद अचानक भीड़ ने दीपू पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

अमृत मंडल को भी भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था

- बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगशा इलाके में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भीड़ द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, मंडल तथाकथित 卐सम्राट वाहिनी卐 समूह का मुखिया था और उस पर जबरन वसूली तथा अन्य आपराधिक मामलों सहित हत्या के दो केस दर्ज थे।रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने उसे तब पकड़कर पीटा जब वह अपने साथियों के संग एक घर से पैसे वसूलने पहुंचा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

योगी मंत्रिमंडल में मकर संक्रांति के बाद फेरबदल!

मुख्य संवाददाता/स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी है। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी इसी क्रम में किया जाएगा। संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अदला-बदली का फार्मूला अपनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल और पश्चिमी महेंद्र कुमार मौजूद रहे। बैठक में यह संकेत मिले कि कुछ मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के सरकार में शामिल होने की संभावना भी चर्चा में रही। साथ ही मनोज पांडेय और पूजा पाल के भी मंत्री बनने के भी आसार है। प्रदेश सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि संसद में चले गए हैं, जिससे रिक्त पदों को नए चेहरे भर सकते हैं। इसके साथ ही आयोगों और बोर्डों में खाली पदों को भरने का निर्णय भी लिया जाएगा।सभी बदलाव जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। पार्टी के भीतर चर्चा है कि पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक है, इसलिए पश्चिम यूपी के नेताओं को आगे लाकर संतुलन बनाने की कोशिश होगी।

- **फेरबदल 2027 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अहम, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ नए चेहरों को मिलेगा मौका**

सिर्फ सेना नहीं, अब जनता की भी सेवा करेगा स्वदेशी हेलीकॉप्टर 'ध्रुव'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बेंगलुरु। अब तक सिर्फ सेना व सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने वाले 'ध्रुव' हेलीकाप्टर का नागरिक संस्करण भी आम लोगों के लिए तैयार हो गया है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित इस नई पीढ़ी के मल्टी-रोल हेलीकाप्टर की पहली नागरिक उड़ान को मंगलवार को नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे भारतीय विमानन इतिहास का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता और एयरोस्पेस सेक्टर में बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है।

मंत्री ने कहा कि पहले एचएएल का झुकाव रक्षा जरूरतों की ओर अधिक था, लेकिन अब सिविल एविएशन में भी नया युग शुरू हो रहा है। ध्रुव का नागरिक संस्करण मेडिकल इमरजेंसी, एयर एम्बुलेंस सेवा, आपदा राहत, पर्यटन और दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना व नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 4,666 करोड़ रुपये के दो अहम सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत थलसेना के लिए 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और नौसेना की पनडुब्बियों के लिए 48 हेवीवेट टॉरपीडो खरीदे जाएंगे। मंत्रालय का कहना है कि इससे देश की सामरिक क्षमताएं और मजबूत होंगी।

- **मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन व दूरदराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा**
- **नागर विमानन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, बोले एयरोस्पेस में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग**

ध्रुव की खासियत

- दो 'शक्ति' इंजनों से लैस यह हेलीकॉप्टर 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है।
- लगातार करीब 3 घंटे 40 मिनट तक उड़ान की क्षमता रखता है।
- इसमें सुरक्षा सीटें, उच्च सुरक्षा फीचर और 14 यात्रियों तक की क्षमता है।
- इसकी अधिकतम गति 285 किमी प्रति घंटा बताई गई है।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर

ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह, सरकारी गनर और 10 अज्ञात भी किए गए नामजद

मुख्य संवाददाता/स्वराज इंडिया

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के स्वास्तिका सिटी इलाके में जमीन कब्जे के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह, उनके सरकारी गनर और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को धमकाया गया, विरोध पर पीड़ित रामू को जातिसूचक शब्द कहे गए और मारपीट भी की गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एसएचओ उपेंद्र सिंह ने पीड़ित पक्ष पर ही एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइनहाजिर कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद मामला पलटा और वायरल वीडियो के आधार पर अब केस दर्ज किया गया है।

- **जमीन कब्जा , एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा, थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने शुरू की जांच**

वीडियो वायरल के बाद बड़ी कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। आरोप है कि कब्जे के दौरान विनय सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लेकर धमका रहे थे और फोन पर बातचीत का वीडियो भी दिया गया। विवाद 4500 स्क्वायर फीट जमीन और पीछे के रास्ते को कब्जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एससी-एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है।